



36

समक्ष : भाननोय राजस्व मेडल म0प्र0 गवालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/ 2016 जवलपुर

हाईटा - 1462-I-16

श्रीमती जानकी बाई भूमियॉ पत्नी देव सिंह निवासी –
ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा जिला जवलपुर म.प्र.

अपीलार्थी

विरुद्ध

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर।
- भागचंद राय पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद राय निवासी
भेड़ाघाट तहसील व जिला जवलपुर।

प्रत्यार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जवलपुर द्वारा प्रकरण क
218 / अ-21 / 2014-2015 अपील मे पारित आदेश दिनांक 08.02.2016
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन
अपील।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपर्युक्तो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम ललपुर तहसील शहपुरा जिला जवलपुर मे रिथति भूमि खसरा नं. 211 एकड़ा 1.690 हे. भूमि अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाऊ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्य कर पुत्री के विवाह एवं अपनी बीमारी का इलाज चल रहा है रूपयो की आवश्यकता हेतु भूमि को विक्य किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्य हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्य की अनुमति दी जाये।
- यहकि, अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विक्य करने के बाद भी अपीलार्थी के पास 5.43 एकड़े भूमि शेष बचना चाही गया है। एवं आवेदित भूमि विक्य पश्चात अपीलार्थी के आर्थिक हितो पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।
- यहकि, माननीय श्रीमान न्यायालय द्वारा भी कई प्रकरणो मे उक्त भूमि विक्य करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि विक्य की अनुमति की आवश्यकता है।

संख्या 1462, ५/१६ (सत्राम्य)

७-६-१६

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्यारा प्र० को 218-अ-21/ 14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-2-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि कलेक्टर जबलपुर के समक्ष आवेदन देकर अपीलांट श्रीमती जानकीवाई ने निजी खाते की ग्राम ललपुर तहसील सहपुरा स्थित भूमि सर्वे को 211 रकमा 1.690 हैक्टर के विकाय हेतु अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 24 अ-21/13-14 पंजीबद्ध किया एंव अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यों की जाँच कराते हुये आदेश दिनांक 19.11.14 पारित करके अपीलांट का आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अपर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 1462-एक/2016 अपील

जिला जबलपुर

तथा
आदेश

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों /
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

आयुक्त, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 218/अ-21/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-2-16 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक श्री सुनील जादौन एंव मोप्रशासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट ने निजी खाते की भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा स्थित भूमि सर्व क्रमांक 211 रकबा 1.690 हैक्टर के विकाय की अनुमति इस आधार पर चाही है कि उसके पास विकाय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त परिवार की गुजर-बसर के लिये पर्याप्त मात्रा में 5.43 हैक्टर भूमि है जिसके कारण अपीलांट भूमिहीन नहीं होगी। भूमि विकाय वह इसलिये कर रही है क्योंकि उसे पुत्री का विवाह करना है एंव बीमारी का इलाज भी कराना है। कलेक्टर द्वारा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जॉच अधीनस्थ राजस्व अधिकारी से कराई है जिन्होंने भी विकाय का प्रयोजन सदभाविक होना बताया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि का भूमिस्वामी भूमि विकाय कर सकता है अथवा नहीं ?

(M)

1/2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 1462-एक/2016 अपील

जिला जबलपुर

प्राप्ति तथा
प्रतिक्रिया

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों /
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र० राज्य तथा अन्य एक 2013 रा०नि० 8 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि –
- (1) भू राजस्व संहिता 1959 (म०प्र०) धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
- (2) विधि का निर्वचन का सिद्धांत – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंध भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।
2. दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामवाई 2004 रा०नि० 183 में व्यवस्था दी गई है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) सरकारी पटटेदार व्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये – भूमि का विक्रय कर सकता है। कलेक्टर की अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्वारा प्रकरण क्रमांक 218/आ.21/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-2-16 तथा कलेक्टर जबलपुर व्वारा प्रकरण क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 1462-एक/2016 अपील

जिला जबलपुर

तथा
दर्तक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों /
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

424/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-11-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्राम ललपुर तहसील शहपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 211 रकमा 1.690 हैक्टर के विकाय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है कि :—

1. भूमि क्य विकाय का दस्तावेज इस आदेश के तीन माह की समयावधि के भीतर कराना अनिवार्य है।
2. भूमि का क्य-विकाय पंजीयन दिनांक को प्रचलित शासकीय गाईड लायन के मान से किया जावेगा।
3. विकाय प्रतिफल विकेता को प्राप्त हो गया है, सन्तुष्टि उपरांत ही उप पंजीयक विकाय पत्र का निष्पादन करेंगे।

सदस्य